बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन

केंद्रीय मुख्यालय

आम हड़ताल : 08 जनवरी, 2020 को

बीएसएनएल में हड़ताल को सफल बनाइए.

नई दिल्ली में 30 सितंबर, 2019 को सम्पन्न राष्ट्रीय खुले व्यापक सम्मेलन में भारत की वर्किंग क्लास को, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की जा रही कॉर्पोरेट समर्थक और कामगार विरोधी नव उदारवादी नीतियों के विरोध में 08 जनवरी, 2020 को आम हड़ताल आयोजित करने का आव्हान किया गया है। 12 और 13 अक्टूबर, 2019 को ग़ाज़ियाबाद में आयोजित BSNLEU की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग में BSNL में आम हड़ताल सफलतापूर्वक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

यह आम हड़ताल क्यों ?

2014 में देश के प्रधान मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि " मैं एक गरीब परिवार से आया हूँ। अतः, मेरी सम्पूर्ण ऊर्जा गरीबों की सेवा में खर्च होगी।" किन्तु, विगत 5 ½ वर्षों का अनुभव साबित करता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नीतियां केवल कॉर्पोरेट समर्थक और कर्मचारी विरोधी है। उदाहरण स्वरूप, जब केंद्रीय श्रम संगठनों ने मांग की थी कि कामगारों की न्यूनतम मजदूरी रु 18,000/- प्रतिमाह निर्धारित की जानी चाहिए, तब नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसे अमान्य कर दिया गया था। किन्तु हाल ही में हमने देखा है कि कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा कर 22% और 15% कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, देश के बड़े कॉर्पोरेट्स को लगभग रु 1,45,000 करोड़ का लाभ हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीव्रता के साथ नव उदारवादी नीतियां लागू करने के चलते, अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। आंकड़े (Statistics) दर्शाते हैं कि भारत में 2017 में 73% नई संपदा, जनसंख्या के शीर्ष 1% द्वारा संग्रहित की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां कॉर्पोरेट समर्थक और कामगार विरोधी है , यह साबित करने के लिए और क्या प्रमाण चाहिए ?

देश के पब्लिक सेक्टर्स पर हमले

जब से 2014 में बीजेपी सत्ता में आई है, भारत के पब्लिक सेक्टर्स पर तीव्र हमले किए जा रहे हैं। भारतीय रेल्वेज का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है। सरकार ने 150 निजी ट्रेन्स जल्द से जल्द शुरू किए जाने की घोषणा की है। साथ ही, सरकार द्वारा रेल्वेज की उत्पाद इकाइयां भी निजीकृत करने हेतु कदम उठाए गए हैं, जिसके विरोध में व्यापक संघर्ष भी हुआ है। देश के सशस्त्र बलों (armed forces) के लिए हथियार और युद्ध सामग्री (ammunitions) निर्मित करने वाली आयुध निर्माणी (ordnance factories) के निजीकरण की ओर भी सरकार द्रुत गति से बढ़ रही है। सरकार की इस पहल के विरोध में अगस्त 2019 में 41ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के 1 लाख से अधिक डिफेंस कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर गए थे। बैंकिंग सेक्टर में सुधार (reforms) के नाम पर मोदी सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 4 बैंक्स में विलीनीकरण कर दिया गया है। बैंक कर्मियों द्वारा, गलत इरादे से (ill-conceived) किए गए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के विलीनीकरण के विरोध में 22 अक्टूबर, 2019 को वृहद रूप से एक दिवसीय हड़ताल की जा चुकी है। सरकार ने भारी मुनाफ़ा कमा रहे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के भी निजीकरण का निर्णय लिया है। वह दिन भी दूर नही जब HPCL और अन्य ऑइल कम्पनीज का निजीकरण किया जा सकता है। 28 नवंबर, 2019 को ऑइल PSUs के निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय व्यापक हड़ताल हो चूकी है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त सभी हड़तालें वर्कर्स की आर्थिक मांगों के लिए न हो कर देश के पब्लिक सेक्टर की रक्षा के लिए हुई है।

वर्किंग क्लास के अधिकारों पर हमले

देश में वर्तमान में जो भी श्रम कानून अस्तित्व में हैं, वे अप्रत्याशित रूप से हासिल नही हुए हैं। वें वर्किंग क्लास के द्वारा काफी संघर्षों पश्चात प्राप्त अधिकार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार इन कानूनों में बदलाव के लिए लगातार कोशिश रत है। "श्रम

कानून संशोधन" के नाम पर, जो भी न्यूनतम सुरक्षा वर्तमान कानून में सुनिश्चित की गई है, उन्हें या तो वापस लिया जा रहा है या नियोक्ता की सुविधा अनुसार कमजोर (dilute) किया जा रहा है। ये श्रम कानून संशोधन और कुछ नही, वरन नियोक्ता को कामगारों के निर्ममता पूर्ण तरीके से शोषण हेतु अतिरिक्त अधिकार देने हेतु उद्देशित है।

BSNL की रक्षा के लिए...

सरकार द्वारा BSNL के लिए रिवाइवल पैकेज की घोषणा की गई है। इस रिवाइवल पैकेज के अनुसार 80,000 कर्मचारियों को VRS के माध्यम से घर भेजा जा रहा है। माननीय संचार मंत्री ने घोषित किया है कि BSNL का निजीकरण या विनिवेशीकरण नही किया जाएगा। किन्तु, इस घोषणा को सतही तौर पर स्वीकार नही किया जा सकता है। BSNL निजीकरण से बच नही सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि मुकेश अम्बानी स्वयं दूरसंचार उद्योग में है। भारतीय पब्लिक सेक्टर की रक्षा के बगैर BSNL की अपने बूते रक्षा संभव नही है।

2017, 2018 और 2019 में 3 हड़तालों के बावजूद BSNL कर्मियों के तृतीय वेज रिवीजन का निराकरण नही हो सका है। BSNL की वित्तीय स्थिति का हवाला दे कर वेज रिवीजन से इंकार , कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय है। साथ ही, वेज रिवीजन से जुड़े होने की वजह से, BSNL के सेवानिवृत्तों के पेंशन रिवीजन का भी निराकरण नही हुआ है। BSNL के रिवाइवल हेतु वित्तीय सहयोग, सीधे भर्ती कर्मियों को 30% सुपरएन्युएशन लाभ, कर्मचारियों के वेतन और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का समय पर भुगतान, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए संघर्ष जरूरी है।

अतः, BSNL की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में रक्षा के लिए और साथ ही हमारी मांगें मनवाने के लिए हम कर्मचारियों का हड़ताल में वृहद रूप से शामिल होने के लिए आव्हान करते हैं।

मांग पत्र

भाग – अ

1) पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज के विनिवेशीकरण/ निजीकरण पर रोक लगाओ ।
2) नियोक्ता के पक्ष में श्रम कानूनों में संशोधन न किए जाएं।
3) राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी रु 21000/- सुनिश्चित करें।
4) मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण हेतु तत्काल कार्यवाही करें।
5) रोज़गार निर्माण कर बेरोजगारी पर नियंत्रण करें।
6) सभी कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवच सुनिश्चित करें, आदि।
7) सभी के लिए सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन रु 10,000/- सरकार के फण्ड के जरिए हो।

भाग- ब

1) BSNL में निजीकरण/ विनिवेशीकरण नही।
2) BSNL कर्मियों के लिए 01.01.2017 से 3rd PRC लागू करें।
3) BSNL नेटवर्क्स के विस्तार/ अपग्रेडेशन और अलाभप्रद ग्रामीण क्षेत्र में सेवाओं हेतु मुआवजे के लिए BSNL को वित्तीय सहयोग प्रदत्त करें।
4) BSNL सेवानिवृत्तों का 01.01.2017 से पेंशन रिवीजन।
5) BSNL के सीधे भर्ती कर्मियों को 30% सुपरएन्युएशन लाभ सुनिश्चित करें।
6) BSNL/ DoT द्वारा BSNL कर्मियों को निर्धारित तिथि पर वेतन भुगतान।
7) कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वेजेस का भुगतान सुनिश्चित करें।

******